प्रकाशनार्थ

पटना 17 मार्च। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट (आद्री) द्वारा **सोशियो–इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स फॉर इडियाज नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स** विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन दिवस पर आज आर.वी. विश्वविद्यालय, बैंगलोर के प्रोफेसर अमित जॉन कुरियन ने उत्तर–पूर्व भारत के गारो हिल्स क्षेत्र के एक गांव में किए गए मानव विकास सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। कृषि में अपनाए गए विकास मॉडल से वनों पर भारी पारिस्थितिक दबाव पड़ रहा है। भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कृषि पद्धतियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए उत्तर–पूर्व क्षेत्र एक केस स्टडी हो सकता है। उन्होंने बताया कि वहां के लोगों के द्वारा भूमि का मुख्य उपयोग झूम खेती ही है और यह उनके जीवित रहने का साधन है। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में वन आच्छादन घट रहा है।

बैंगलोर की एक स्वतंत्र शोधकर्ता डॉ. ए.आर. वासवी ने बताया कि भारत में कृषि संकट मौजूद है। एक ग्रामीण मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, लेकिन कई छोटे किसान अपने भूखंडों को बेचकर या खेती को छोड़कर कृषि से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। इस सत्र की अध्यक्षता पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना के निदेशक प्रोफेसर एस.के. भौमिक ने की।

अगले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता सीएनटी आर्किटेक्ट्स, बैंगलोर के डॉ. प्रेम चंद्रावरकर ने की। इस सत्र में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीच्यूट (डब्ल्यूआरआई) इंडिया की निदेशक डॉ. शाहाना चटराज ने इस बात पर जोर दिया कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है। उन्होंने बताया कि कैसे जुगाड़ पूरे भारत में एक व्यापक प्रथा है। यह तब सामने आया है जब बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाएं प्रदान करने में राज्य की विफलता के साथ कुछ नया करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि आधार जैसी चीजों के कारण भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोगों की निगरानी करने वाला देश है।

कार्यशाला का अंतिम संबोधन टेक्नोलॉजिकल चेंज लैब की शोधकर्ता डॉ. स्मिता श्रीनिवास द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि हम एक असाधारण गतिशीलता वाले राष्ट्र में रहते हैं जिसे फील्ड–आधारित अनुसंधान के माध्यम से देखा जाता है। हालांकि, फील्ड में सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर है, जो हमारे मानक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि फील्ड में इस व्यावहारिक गतिशीलता को सैद्धांतिक रूप देने से हमें अगले 30 वर्षों के लिए विश्व आर्थिक प्रणालियों में बदलाव की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है।

इस कार्यशाला में योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ अरुणीश चावला ने भाग लिया और प्रतिभागियों के साथ विचार–मंथन किया। इस कार्यशाला में कई स्थानीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षाविदों ने भाग लिया। आद्री की डा. सुनीता लाल ने वक्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए और डा. अस्मिता गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

(अंजनी कुमार वर्मा)